3 न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है: साय

5 दबंग महिला नेत्री है उमा भारती

5 होली: अंतर्मन के रंगों का उत्सव

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 45 प्रति सोमवार, 17 मार्च 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

एक ही भाजपा के दो रूप- मोदी खुद को जनता का सेवक बताते हैं और प्रहलाद जनता को भिखारी

▪ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने जैसा घिनौना अपराध किया है पटेल ने

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों उफान पर है। सरकार में पंचायत और श्रममंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पिछले दिनों दिए गए भीख वाला बयान सुर्खियों में छाया हुआ है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पटेल ने राजगढ़ के सुठालिया में लोधी समाज के एक सम्मेलन में जनता द्वारा दिए जाने वाले मांग पत्रों को 'भीख' कह डाला। इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई। बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति पर भी सवालियां निशान खड़ा कर दिया है। मंत्री पटेल ने मताधिकार का उपयोग करने वाली जनता को भिखारी बताकर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मंत्री पटेल को इसी तरह की बयानबाजी करने और प्रदेश सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मध्यप्रदेश भेजा। क्योंकि मंत्री पटेल जबसे मध्यप्रदेश आए हैं वह किसी न किसी रूप में

व्यवस्था देखी थी। लेकिन उस व्यवस्था से भारत ने यह सीखा था कि अगर सौभाग्यवश अच्छा राजा मिल गया तो प्रजा की सुनवाई होगी नहीं तो राजा अपने भोग-विलास में लीन रहेगा और प्रजा का शोषण करता रहेगा। जनता को कभी भी अपना राजा 'चुनने' का अधिकार नहीं मिला था।

किसके पास जाएगी जनता अपनी बात कहने

अगर प्रह्लाद पटेल को जनता से इतना ही परेशानी है तो उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि जनता चुनाव के बाद अपने से जुड़ी किसी भी परेशानी के निराकरण के लिए जनप्रतिनिधि के पास ही जाएगी। आखिर जनप्रतिनिधि उन्हीं के बीच का वह व्यक्ति है जिसे जनता मताधिकार का उपयोग करके विधानसभा या संसद तक पहुंचती है। ऐसे में जनप्रतिनिधि को यह बात कहने का कोई अधिकार नहीं कि वह उसे भिखारी कहकर संबोधित करे। यही नहीं यह वही जनता है जो मताधिकार के प्रयोग से संसद तक पहुंचा सकती है तो राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर अपना विरोध भी दर्ज करवा सकती है जिससे जन प्रतिनिधि को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ाया महत्वपूर्ण कदम

-विजया पाठक

प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश की जनता के लिए निरंतर प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ रहे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव का मानना है कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आर्शीवाद से

छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा मे तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार को अभी तेरह महीने ही हुए है। इस बीच हमने सुशासन के लिए, संवेदनशीलता के साथ, जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के साथ ही हम लोगो ने सभी वर्गों के विकास के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। इससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं मे वृद्धि हुई है। हमारा पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए समर्पित रहा। प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे है। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियो को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है।

नगरीय क्षेत्र का समन्वित विकास

मुख्यमंत्री के अनुसार देश के मुखिया प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि होंगे तो सबका साथ, सबका विकास मूलमंत्र के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव और नगरीय क्षेत्र का समन्वित विकास होना चाहिए, इसके लिए मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में लम्बे समय से मांग की जा रही थी। हमने संवेदनशीलता के साथ विचार कर इसके लिए नए पद भी स्वीकृत किए हैं। नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में हम लोग आज 103 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश पत्र अभी वितरण किए हैं। (शेष पेज 2 पर)

सरकार और अफसरों की उदासीनता के कारण अग्निवीर भर्ती के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पा रहे संस्कृत विद्यालय के छात्र

आखिर संस्कृत विद्यालय और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है?

-विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिला है। दरअसल केन्द्र सरकार द्वारा देश के हर राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किया जाता है। इन संस्कृति विश्वविद्यालय में देश के लाखों युवा अपने सपनों को पंख लगाने के उद्देश्य से इसमें एडमिशन लेते हैं और तीन से चार साल तक लगातार पढ़ाई करते हैं। लेकिन युवाओं का यह परिश्रम बेकार होता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल संस्कृत विश्वविद्यालय से मध्यम और प्राकशाशास्त्री कर नौकरी की तलाश में अग्निवीर भर्ती में पहुंचे युवाओं की शैक्षणिक अर्हता को रद्द कर दिया गया। यानि अग्निवीर जैसी शासकीय भर्ती में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय से पास हुए छात्रों की मार्कशीट मात्र कचरा बनकर रह गई है। (शेष पेज 6 पर)

जनगण को भिखारी शब्द के साथ संबोधित करने का अधिकार पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को किसने दिया

▪ प्रहलाद पटेल बताएं क्या जनता ने अपनी बात जनप्रतिनिधि के होने नाते रखी तो क्या गलत किया?

(पेज 1 से जारी)

पटेल क्यों जाते हैं जनता से वोट मांगने?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पटेल ने जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। यह वही स्वाभिमानी जनता है जो आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आपको लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाती है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रजा को अपमानित करना भला कहा का न्याय है। खैर, यदि पटेल को जनता एक भिखारी के स्वरूप में दिखाई देती है तो फिर पटेल चुनाव के समय खुद क्यों जनता के दरवाजे पर भीख मांगने जाते हैं। आखिर सबसे बड़ा भिखारी कौन है सबसे पहले मंत्री पटेल यह स्पष्ट करें।

कमलनाथ ने की बयान की निंदा

मंत्री प्रह्लाद पटेल के बयान पर कांग्रेस ने खासी निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रहलाद

को निम्न स्तर के सोच का व्यक्ति बताया। वरिष्ठ नेताओं ने यह तक कहा अगर समाज की राजनीति करनी है तो इस्तीफा दो। मंत्री पटेल का यह बयान भावनात्मक रूप से ठीक नहीं था। जनता अपनी मांगें सरकार के सामने रखती है क्योंकि वह आपको एक उम्मीद के रूप में देखती है। जनता लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है। इसे 'भीख' कहना न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मंत्री शायद जनता की भावनाओं से कटे हुए हैं। एक मंत्री को अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। 'भीख' जैसे शब्द का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रूप से नहीं किया जा सकता है।

मोदी खुद को बताते हैं जनता का सेवक

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को जनता का सेवक बताते हैं तो दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल का यह बयान कहीं न कहीं भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान है। उल्लेखनीय है कि मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के साथ खुद को जनता का सेवक बताया था और यह वायदा किया था कि वह और उनकी सरकार का प्रत्येक मंत्री सेवक के रूप में जनता की सेवा करेगा।

बिहार तक पहुंचा पटेल का विवाद

पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल का बयान बिहार पहुंच गया है। वहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। याद दिलाने की जरूरत नहीं कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन यहां याद दिलाने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव 2024 में, उत्तर प्रदेश के एक प्रत्याशी द्वारा दिए गए बयान ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में नुकसान पहुंचा दिया था। इससे पहले के लोकसभा चुनाव 2014-2019 में कांग्रेस पार्टी के एक नेता द्वारा दिए गए बयान ने, पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया था।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ाया महत्वपूर्ण कदम

(पेज 1 से जारी)

हमारा प्रयास है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर हों। हमारी सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

70 कार्यों का किया लोकार्पण

प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास और 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण अभी यहां पर हुआ है। 06 नगरीय निकायों तखतपुर, रतनपुर, भानुप्रतापुर, छुरिया, मल्हार ओर खोंगापानी में अमृत मिशन-2.0 के तहत 270 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी हम लोगों ने यहां पर किया है। इन नगरीय निकायों में 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प मूर्तरूप लेने वाला है। स्वच्छ भारत अभियान में सभी की सहभागिता से नगरीय क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिल रही है। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समय-समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे ही मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 14 नगरीय निकायों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी आदि नगरीय निकायों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें सम्मानित करके हम खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

08 हजार रुपये मिलेगा मानदेय

शहरों में स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने में स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान है। इनके लगन और मेहतन से ही स्वच्छता मिशन सफल हो पा रहा है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान, इनके योगदान को प्रोत्साहन देता है। हम इनका सम्मान करके खुद भी सम्मानित

महसूस कर रहे हैं। राज्य के नगरीय निकायों में इस समय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 09 हजार से अधिक स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं। इन्हें 7200 रुपये मानदेय दिया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि स्वच्छता दीदियों के मानदेय में 800 रूपये की बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब स्वच्छता दीदियों को हर महीने 08 हजार रूपये मानदेय मिलेगा।

हर नागरिक को मिलेगा पक्का मकान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। मोदी जी की गारंटी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनते ही, हमने 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी का लिया। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डबल इंजन की सरकार में भरपूर सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें दुर्ग में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने 03 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति भी दी है। प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस योजना में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। इसका लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा, जिनके पास दोपहिया वाहन है। जिनके पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक असिंचित खेती है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और सुगम सर्वेक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। अब घर बैठे ही मोबाइल एप के माध्यम से पात्रता संबंधी पंजीयन करा सकते हैं।

10 हजार रुपये देने की व्यवस्था की

मोदी जी की एक गारंटी प्रदेश के पांच लाख से अधिक भूमिहीन श्रमिकों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन श्रमिक योजना अंतर्गत 10 हजार रूपये देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज के कार्यक्रम में माता-बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। यह इस बात का प्रमाण है कि इनके खाते में हर महीने एक-एक हजार रूपये आ रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काम करने वाली और सुशासन की सरकार है। विष्णु के सुशासन में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में लगातार विकास की गंगा बह रही है।

न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है और अधिवक्ताओं की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ न्याय प्रक्रिया को तेज करने में योगदान देना चाहिए, ताकि समाज के सबसे वंचित तबके को भी न्याय सुलभ हो सके। जशपुर जिला व्यवहार न्यायालय में आयोजित जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बात कही। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें न्यायिक सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प दिलाते हुए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बार काउंसिल के जीर्णोद्धार एवं ई-लाइब्रेरी निर्माण के लिए 01 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे, विधायक श्रीमती गोमती साय और श्रीमती रायमुनी भगत सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शपथ ग्रहण करने वालों में अध्यक्ष ओम प्रकाश साय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद सिन्हा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती दीपिका कुजूर, सचिव सत्य प्रकाश तिवारी, सह सचिव सूरज चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुचेन्द्र कुमार सिंह, ग्रंथपाल गोपाल प्रसाद रवानी और क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव सत्येन्द्र जोल्हे शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने जशपुर जिला अधिवक्ता संघ के ऐतिहासिक

योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि यह संघ हमेशा से सामाजिक न्याय और विधिक सेवा में अग्रणी रहा है। उन्होंने श्री भारतचंद काबरा, श्री बालासाहेब देशपांडे और श्री नरहरि साय जैसी विभूतियों का स्मरण करते हुए कहा कि इन सभी ने शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे इस परंपरा को बनाए रखते हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और उनके लिए न्याय की राह को सुगम बनाएं।

बार काउंसिल के जीर्णोद्धार एवं ई-लाइब्रेरी के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिवक्ताओं के लिए सुविधा और संसाधनों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बार काउंसिल के जीर्णोद्धार और ई-लाइब्रेरी के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में ई-लाइब्रेरी से अधिवक्ताओं और कानून के छात्रों को नवीनतम विधिक जानकारी और अद्यतन संदर्भ सामग्री तक सहज पहुंच प्राप्त होगी। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ेगी और नए अधिवक्ताओं को अध्ययन व अनुसंधान के बेहतर अवसर मिलेंगे।

न्यायपालिका और अधिवक्ता संघ का अटूट रिश्ता – प्रधान जिला न्यायाधीश

इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मंसूर अहमद ने कहा कि न्यायपालिका और अधिवक्ता संघ के बीच अटूट रिश्ता है, और दोनों को मिलकर समाज में न्याय और विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ताओं को न्याय की गरिमा बनाए रखने और विधिक सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की अपील की। इस अवसर पर वक्ताओं ने अधिवक्ताओं की समाज में भूमिका, विधिक सहायता की आवश्यकता और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार साझा किए। शपथ ग्रहण समारोह में कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, पवन साय, कृष्ण कुमार राय, रामप्रताप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एम्स भोपाल की डॉ. ऋषिका ए को सर्जिकल देखभाल में एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप पर शोध के लिए आईसीएमआर पीजी थीसिस अनुदान प्राप्त

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह संस्थान में शैक्षणिक श्रेष्ठता और ज्ञान के आदान-प्रदान को एक प्रेरक परंपरा के रूप में विकसित कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से संकाय सदस्य और छात्र निरंतर उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाल ही में, एम्स भोपाल के फार्माकोलॉजी विभाग की तृतीय वर्ष की स्नातकोत्तर (एमडी) छात्रा, डॉ. ऋषिका ए को आईसीएमआर पीजी थीसिस ग्रांट से सम्मानित किया गया है। यह अनुदान उनके शोध अध्ययन "सर्जिकल एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलैक्सिस (SAP) का मूल्यांकन और स्वच्छ एवं अर्ध-स्वच्छ सर्जरी से गुजरने वाले रोगियों में एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप हस्तक्षेप के कार्यान्वयन का प्रभाव" पर आधारित है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने डॉ. ऋषिका ए को बधाई दी और उनके शोध की सराहना करते हुए कहा: "डॉ. ऋषिका का अध्ययन एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अनुसंधान-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) को संबोधित करना स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। आईसीएमआर द्वारा यह मान्यता वैज्ञानिक अनुसंधान की नीति निर्माण और नैदानिक अभ्यासों को दिशा देने में महत्त्व को दर्शाती है।" यह शोध डॉ. बालकृष्ण एस., प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, एम्स भोपाल एवं डॉ. शिल्पा एन. काओरे, प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य सर्जिकल प्रक्रियाओं में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करना, सर्जिकल साइट संक्रमण (SSIs) को कम करना और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) से लड़ना है। यह अध्ययन प्रशिक्षण एवं शिक्षा, संभावित ऑडिटिंग और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच फोकस ग्रुप चर्चा जैसी हस्तक्षेप रणनीतियों पर केंद्रित है, जिससे राष्ट्रीय (आईसीएमआर) और वैश्विक (WHO) एंटीमाइक्रोबियल दिशानिर्देशों के अनुपालन को बढ़ावा दिया जा सके।

राजस्व विभाग से सभी परेशान, गरीबों की जिंदगी निकल जाती है लेकिन वो खुद की जमीन नहीं ले पाते

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला।मप्र के राजस्व विभाग का यह हाल की लोग केवल दर दर केवल शिकायत ही करते रहते है लेकिन कभी कोई निराकरण नहीं होता चाहे 181 पर शिकायत करो। अधिकारी जबरजस्ती पीड़ित की शिकायत बंद करते हैं। ऐसा ही एक मामला सागर जिले की देवरी से जुड़ा हुआ है, जहां ग्राम मुर्रई में दिनेश पिता मोहनसिंह के नाम 2022 में 1.92 हेक्टेयर दर्ज थी और इसी जमीन पर सेंटल बैंक ऑफ इंडिया से केसीसी लॉन भी किसान ने लिया था लेकिन जब सरकार का स्वामित्व योजना का सर्वे हुआ तो उसकी जमीन को ब्लाक कर दिया गया जिसकी शिकायत किसने ने बीते 3 सालों में कलेक्टर, एसडीएम और 181 पर भी की लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुए और 181 की शिकायत जबरजस्ती अधिकारियों ने बंद करा दी। जब पीड़ित इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक बृजबिहारी पटेरिया के पास गया तो विधायक ने आवेदन पर टीप लगाई कि इसकी जमीन ब्लॉक से हटा दी जाए लेकिन फिर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सकल पंच राठौर समाज की बैठक संपन्न, कैलाश ठेकेदार अध्यक्ष बने

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। सकल पंच राठौर समाज की बैठक स्थानीय राठौर धर्मशाला में सम्पन्न हुई, जिसमें वर्तमान समाज के संचालन समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर उपस्थित, समाजजनों ने नया अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर कैलाश ठेकेदार एवं उपाध्यक्ष पद पर जगदीश दाल बाटी को नियुक्त किया गया। शेष पदाधिकारी का गठन समाज के वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन में उपरोक्त दोनों द्वारा किया जाएगा। नव नियुक्त अध्यक्ष कैलाश ठेकेदार एवं उपाध्यक्ष जगदीश दाल बाटी ने बताया कि समाजजनों द्वारा हमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया। हम कार्यकारिणी के शेष पदाधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति कर आगामी हमारे कार्यकाल समाज के वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन में एवं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर समाज के हित में कार्य करने का फर्ज पूरे तन मन धन समर्पित होकर निभाएंगे।

ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक फैला सूदखोरी का मकड़जाल

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। शहरी क्षेत्र समेत ग्रामीण अंचलों में सूदखोरी का मकड़जाल फैला हुआ है, भले ही शासन के निर्देश पूर्व में प्रशासनिक तौर पर कार्यवाही को लेकर अभियान चलाया था लेकिन शिकायतकर्ताओं के सामने नहीं आने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही हैं। जिससे सूदखोरी के हौसले बुलंद हैं। बताया जाता है कि जरूरतमन्द को रुपये की जरूरत होने पर ब्याज के तौर पर कथित लोगों द्वारा राशि दी जाती है। मूल धनराशि पर मन माना ब्याज वसूलते हैं, यहां तक कि लोगों की भूमि तक को गिरवी रख लेते हैं, और ब्याज की राशि बढ़ाकर जमीन की रजिस्ट्री करने को मजबूर कर देते हैं, जिले भर में सूदखोरी का यह गोरखधंधा, काफी हद तक फलफूल रहा है, पीडितों के सामने नहीं आने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती है। सबसे ज्यादा सूदखोरी के शिकार गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोग हो रहे हैं, ब्याज की राशि वसूलने को लेकर हर महिने पीडितों को परेशान किया जाता है, जिले भर में चल रहे सूदखोरी के गोरखधंधा पर कड़ाई से लगाम लगाए जाने की जरूरत है।

सम्पादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद उठे प्रश्नचिन्ह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमाका करते हुए स्टील और अल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यह टैरिफ उन सभी देशों पर लागू होगा, जो अमेरिका को स्टील और अल्युमिनियम निर्यात करते हैं। खास बात यह कि इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं देशों को होने वाला है, जो अमेरिका के मित्र देशों की श्रेणी में आते हैं। ट्रंप बार-बार कहते रहे हैं कि वह अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं और उनकी नजरें सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रीय हितों पर हैं। लेकिन अगर इस एक कसौटी पर देखें तो भी उनके फैसले सवालों के घेरे में आते हैं। इसलिए भी क्योंकि सभी संबद्ध पक्षों से बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए राह बनाने के बजाय वे इकतरफा फैसले की ऐसी शैली अपना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों का ही नुकसान होगा।

स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ के ताजा फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले कनाडा जैसे देशों ने तो जवाबी कार्रवाई की बात कही ही है, यूरोप ने भी तत्काल 28 बिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। संकेत हैं कि तत्काल लिए गए फैसलों के अलावा ये देश उन संभावित फैसलों पर विचार कर रहे हैं, जिनसे अमेरिका को उतना नुकसान हो कि वह बातचीत की मेज पर आए। ताजा फैसले को लें तो अमेरिका में स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन स्टील और अल्युमिनियम महंगा होने से कार, टिन कैन, सोलर पैनल बनाने वालों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। पिछले कार्यकाल के दौरान 2018 में लिए गए ट्रंप के ऐसे ही फैसले की बदौलत वहां 2021 तक स्टील उत्पादन 2% बढ़ा, लेकिन इसी अवधि में अन्य सेक्टरों में उत्पादन में 3.48 बिलियन डॉलर मूल्य के बराबर कमी दर्ज की गई। वहीं, भारत ट्रंप के टैरिफ को लेकर किसी निर्णय की जल्दबाजी में नहीं है। दोनों देशों के बीच यूं भी व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, जिसे पूरा होने में समय लग सकता है। वहीं, ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसलों से अमेरिका के मंदी में जाने की आशंका पैदा हो रही है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, इसलिए ऐसा होने पर ग्लोबल इकॉनमिक ग्रोथ सुस्त पड़ सकती है।

सियासी गहमागहमी

भाजपा नेताओं की तरसने लगी आंखें

मध्यप्रदेश भाजपा में पिछले लगभग आठ महीने से प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की कवायद चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऊपर से पर्दा नहीं हट सका है। नये प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं की आंखें झुक गई हैं। हर कोई इस बात की सोच में डूबा हुआ है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर से पर्दा कब हटेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर भाजपा शीर्ष दल प्रदेश अध्यक्ष के पद के नाम की घोषणा कब करता है या फिर अभी संशय आगे भी बरकरार रहेगा।

बघेल की कम नहीं हो रही मुश्किलें

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेड के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया है। माना जा रहा है कि, जवाब से संतुष्ट न होने पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि बघेल और उनका बेटा ईडी के इस शिंकजे से मुक्त होने के लिए क्या पैंतरा अपनाते हैं। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में बघेल के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने की आशंका है। हालांकि बघेल अपने तरीके से इस पूरे चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलहाल राहत मिलती दिख नहीं रही है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक महीने से अधिक हो गया है।
मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगें की थीं, वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश कानून अव्यवस्था की राजधानी बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बनता जा रहा है। पूरा देश आज मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है और ये हालात है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

दबंग महिला नेत्री के रूप में भाजपा को विशिष्ट पहचान दिलाने में सफल हुई उमा भारती

समता पाठक/जगत प्रवाह

उमा भारती भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है, जो हिंदुत्व की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और विवादों के लिए जाना जाता है। साध्वी के रूप में अपनी धार्मिक छवि से लेकर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने तक उनका सफर प्रेरणादायक और घटनाओं से भरा रहा है। उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के डुंडा गांव में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने कक्षा छठवीं तक पढ़ाई की थी। वह लोधी जाति से आती हैं। उनका परिवार धार्मिक विचारधारा से प्रभावित था। बचपन से ही उमा भारती में आध्यात्मिक झुकाव देखा गया। उन्होंने शिक्षा में कोई औपचारिक डिग्री हासिल नहीं की। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में उनकी गहरी रुचि रही। छोटी उम्र से ही उन्होंने धार्मिक सभाओं में प्रवचन देना शुरू कर दिया और साध्वी के रूप में पहचानी जाने लगीं। उमा को मध्यप्रदेश की राजनीति का ऐसा चेहरा माना जाता है, जिसने राज्य में 10 साल तक काबिज कांग्रेस की सत्ता को जड़ से हटाया और राज्य में भाजपा की जड़ें जमाईं। उमा भारती का यह प्रभाव है कि उन्होंने राज्य में भाजपा की ऐसी जड़ें जमाईं कि आज भी मध्य प्रदेश की सत्ता पर भाजपा का कब्जा है। उमा ने सिर्फ छठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उनको बचपन से ही हिंदू धर्म ग्रंथों का शौक था। इसलिए उमा भारती ने बचपन से ही हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। वह अविवाहित हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार-प्रसार में लगा दिया। वहीं वह अब तक तीन किताबें भी लिख चुकी हैं। उमा भारती ने ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सानिध्य में अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत की थी। वहीं राम जन्मभूमि को बचाने के लिए उमा ने पार्टी से निलंबन के बाद भोपाल से अयोध्या तक कठिन पद-यात्रा की। फिर साध्वी ऋतंभरा के साथ उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। साल 2007 में उमा भारती ने रामसेतु को बचाने के लिए सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के विरोध में 5 दिन तक भूख हड़ताल भी की।

साल 1984 में उमा भारती ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन इस दौरान उनको हार का सामना करना पड़ा था। साल 1989 में उन्होंने खजुराहो से दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार उनको जीत हासिल हुई। फिर साल 1991, 1996 और 1998 में उमा ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रहा। इसके बाद साल 1999 में वह भोपाल सीट से सांसद निर्वाचित हुईं। इसके अलावा वह वाजपेयी सरकार में उमा भारती पर्यटन, युवा मामले एवं खेल, मानव संसाधन विकास और अंत में कोयला और खदान जैसे कई राज्य स्तरीय और कैबिनेट स्तर के पदों का कार्यभार संभाला। साल 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था। उस दौरान 10 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज दिग्विजय सिंह को सत्ता से हटाने में उमा भारती ने अहम भूमिका निभाई। बता दें कि राज्य से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए भाजपा ने तत्कालीन कोयला मंत्री उमा भारती को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद उमा ने फौरन केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उमा भारती ने राज्य में भाजपा की ऐसी जड़ें जमाईं, जिससे दिग्विजय सिंह की सत्ता का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही पार्टी ने उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह से उमा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थीं। उमा भारती सिर्फ 8 महीने मुख्यमंत्री पद पर रहीं, इसी दौरान साल 1994 में एक मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। यह वारंट हुबली कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था। जिसके बाद उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा।

होली: अंतर्मन के रंगों का उत्सव

- प्रकृति के सौंदर्य से जीवन में उमंग भरता है त्यौहार
- गिले शिकवे भूलकर रिश्तों की करें नई शुरुआत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

होली, रंगों का त्योहार है, प्रकृति के सौंदर्य के बीच यह हमारे जीवन में उमंग भरता है। यह सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन को भी रंगीन बनाने का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम अपनी बुराइयों को जलाकर, अपने मन को प्रेम और खुशियों के रंगों से भर सकते हैं। गिले-शिकवे भूलाकर रिश्तो की नई शुरूआत का भी यह बेहतरीन अवसर है। भारतीय परंपरा में हर त्यौहार के साथ प्रकृति का जुड़ाव है और मौसम का बड़ा महत्व है। फाल्गुन के महीने में, जब प्रकृति रंगों से सराबोर होती है, तो होली का त्योहार मनाया जाता है। पेड़ों पर टेसू के फूल खिलते हैं, ठंड जा चुकी होती है और गर्मियों का मौसम दस्तक दे रहा होता है। खेतों से फसलें घर आ चुकी होती हैं और किसानों के चेहरे पर मुस्कान होती है। ऐसे में, होली का उत्सव हमें बताता है कि हमें अपने आंतरिक जीवन में भी रंगों को भरना चाहिए और उत्साह और उल्लास के माहौल में जीवन को जीना चाहिए।

बुराई पर अच्छाई की विजय:

पौराणिक कथाओं के अनुसार, होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, प्रह्लाद को जलाने के लिए अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है।

प्रेम, सौहार्द और करुणा और दया के रंग:

होली हमें अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का अवसर देती है। जिस प्रकार हम बाहरी रंगों से अपने जीवन को रंगीन बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन को भी प्रेम, सौहार्द, करुणा और दया के रंगों से भरना चाहिए। जब हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है, तो बाहरी दुनिया भी हमें रंगीन दिखाई देती है।

जीवन में सकारात्मकता का संचार:

होली हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करना चाहिए। हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालकर, सकारात्मक विचारों को स्थान देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जीवन आनंद और खुशियों से भर जाता है।

एक सामाजिक पर्व:

होली एक सामाजिक पर्व भी है। यह हमें एक-दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ मनाने का अवसर देता है। इस दिन हम अपने गिले-शिकवे भुलाकर, एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और प्रेम का संदेश फैलाते हैं।

भारत की विविधतापूर्ण होली:

भारत में होली का उत्सव अलग-अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली, बरसाने की लठमार होली, मथुरा और वृंदावन की होली, कुमाऊँ की गीत बैठकी, छत्तीसगढ़ की होरी, मध्यप्रदेश के भगोरिया, हरियाणा की धुलंडी, महाराष्ट्र की रंग पंचमी, गोवा का शिमगो, पंजाब का होला मोहल्ला, बिहार का फगुआ सभी अपने आप में अनूठे हैं।

होली हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को प्रेम, खुशियों और सकारात्मकता के रंगों से भरना चाहिए। यह हमें अपने अंतर्मन को शुद्ध करने और बुराइयों को जलाने का अवसर देती है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक पर्व भी है जो हमें एक-दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ मनाने का अवसर देता है।

आतंकियों की चपेट में पाकिस्तान

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) द्वारा पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रेल अपहरण के बाद तय हो गया है कि पाकिस्तान अब अपने ही देश के आतंकवादी संगठनों की चपेट में आता जा रहा है। पाकिस्तान की यह दुर्गति 'बोज बोए बबूल के, आम कहां से होएं' कहावत को चरितार्थ करने वाली है। पाकिस्तान की यह दशा आतंकवादियों को पालने-पोसने का परिणाम है। ये संगठन जिस तेजी से पाक में हमलावर बने हुए हैं, उसके चलते ऊंट अब पहाड़ के नीचे आता जा रहा है। बलूचों के हमले के बाद तहरीक-ए-पाकिस्तान (टीटीपी) ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि पाक सेना एक कैंसर है, इसे नहीं छोड़ेंगे। टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान-अफगानिस्तान के सीमाई क्षेत्र में जारी है। 2007 में जन्मा टीटीपी 13 आतंकी समूहों का एकीकृत संगठन है। 2014 में इसी ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके 126 छात्रों को मार डाला था। टीटीपी के अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान (आईएसके) भी वर्तमान में मजबूत हो गया है। ये तीनों संगठन परस्पर संगठित होकर पाक के लिए सिरदर्द बन गए है। इसी का नतीजा है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाक इस साल दूसरा सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश बन चुका है।

बीएलए ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित बड़ा अलगाववादी संगठन है। बलूचिस्तान क्षेत्र के पाक के कब्जे के आने के बाद से ही आजादी के लिए संघर्षरत है। जबकि अंग्रेजों ने इसे स्वतंत्र देश मान लिया था। लेकिन पीओके के साथ पाक ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया था, तब बलूचिस्तान पाक के मानचित्र में शामिल नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत ने बलूचिस्तान को कुछ कबाइली क्षेत्रों और कुछ स्वतंत्र रियासतों में बांट दिया था। इस स्थिति में कबाइली सरदार अकबर बुगती ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। इस फैसले के साथ मकरान, खारान और लसबेला रियासतों ने तो पाक में विलय होने की सहमती दे दी, लेकिन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत कलात ने स्वतंत्र सूबा के रूप में बने रहने का निर्णय लिया। नतीजतन 1948 में कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन शाही परिवार के प्रिंस करीम ने आजादी के लिए सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इससे निपटने के लिए 1948 में बलूचिस्तान में पाक ने पहला सैन्य अभियान चलाकर सशस्त्र खिलाफत को अपदस्थ किया। किंतु आगे भी बलूचिस्तान में विद्रोह फूटते रहे, जिसके फलस्वरूप 1970 में बलूचिस्तान को स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दे दिया गया। यहां निर्वाचित सरकार भी बनी। जिसे 1973 में बर्खास्त कर दिया गया। तभी से यह क्षेत्र स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। परंतु सैनिक तानाशाह जियाउल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबख्श मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ी हुई। इसके बाद से ही जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारें के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान में कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते थे। अतएव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्ष पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ हैं। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी। जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलूचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसीलिए वे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तभी से यह संगठन पाक सेना से लोहा ले रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर भी हमला इसलिए बोला गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पाक सैनिक यात्रा करते हैं।

गिलगित और बलूचिस्तान पर पाक ने 17 मार्च 1947 को सेना के बूते अवैध कब्जा कर लिया था, तभी से यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाज उठाने वाले लोगों पर दमन और अत्याचार आज तक जारी है। अब इस लड़ाई में टीटीपी और आईएसके भी पाक पर हमलावर के रूप में पेष आ रहे हैं। पाक की कुल भूमि का 40 फीसदी हिस्सा यहीं है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 01 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच है। यहां हिंदु, सिख और ईसाई भी रहते हैं। इनमें आपस में खूब भाईचारा है। भगवान शिव की पत्नी सती का हिंगलाज मंदिर इसी बलूच क्षेत्र में आता है। अनेक मुसलमान भी देवी सती की पूजा-अर्चना करते हैं। क्योंकि ये मतांतरित हिंदु हैं। यहां से कभी सांप्रदायिक दंगे की खबरें नहीं आती हैं। 1977 में पाक द्वारा दमन के बाद करीब 2 दशक तक शांति रही। लेकिन 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। कड़सके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बीएलए ही है। पीओके और बलूचिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। इसे ही पीओके कहा जाता है। पाक के लिए यह पूरा क्षेत्र बहिष्कृत हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह, जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है, वहीं बलूचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है। लेकिन अब कई आतंकी संगठनों ने मिलकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

सरकार और अफसरों की उदासीनता के कारण अग्निवीर भर्ती के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पा रहे संस्कृत विद्यालय के छात्र

(पेज 1 से जारी)

उल्लेखनीय है कि देश में संस्कृत शिक्षा के लिए कुल 18 विश्वविद्यालय और 760 कॉलेज हैं, जिनमें 3 केंद्रीय, 1 डीम्ड और 14 राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।

लाखों युवाओं के साथ हुए इस धोखे का जिम्मेदार कौन?

देश में ऐसे लाखों युवा हैं जो संस्कृत विद्यालय और विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेकर विभिन्न कोर्स में पढ़ाई करते हैं। लेकिन भोपाल के संस्कृत विश्वविद्यालय से सामने आये इस मामले ने लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। अब युवाओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह अपनी गुहार किसके पास लगाये। क्योंकि उनके साथ हुए इस धोखे की शिकायत वह कहां और किसके पास करें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने इतने दिनों तक इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया और न ही इस दिशा में कभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

केंद्र के आदेश के बाद भी मान्यता नहीं दे रहे बोर्ड

भोपाल के आर्यावर्त शर्मा ने 2024 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल कैंपस से कक्षा 12वीं (प्राक्शास्त्री) की पढ़ाई की, लेकिन इसे मान्यता न मिलने के कारण किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल रहा। वे सीयूईटी और अग्निवीर भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और केंद्रीय संस्कृत विवि का नाम उपलब्ध नहीं। अब उन्हें प्राइवेट 12वीं की पढ़ाई करनी पड़ रही है। समाधान के लिए कैंपस में कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली।

1970 में देशभर में हुई थी संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना

भारत सरकार ने 1970 में संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की थी। मई 2002 में इसे बहु परिसरीय मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया, जिसका भोपाल कैंपस साल 2002-03 से संचालित है। 2020 में इसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शामिल कर दिया गया। 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और बोर्ड को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया था कि उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्त्री 11वीं और 12वीं के समकक्ष है, फिर भी कई संस्थान इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं।

जम्मू कश्मीर के संस्कृत विद्यार्थी भी रोजगार के लिए परेशान

जम्मू कश्मीर के संस्कृत स्कॉलरों ने अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंतित है। स्कॉलर्स का कहना है कि यदि संस्कृत के साथ यही भेदभाव किया गया तो वे इस भाषा में पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। कई शोधकर्ताओं ने यहां तक कहा कि उन्हें इस भाषा के माध्यम से सरकारी नौकरी में उनका हक नहीं दिया जा रहा है। बाबा कैलख देव स्थान के महंत रोहित शास्त्री के अनुसार राज्य सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय कोट भलवाल की डिग्रियों को मान्यता नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मान्यता प्राप्त यह विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से राज्य में चल रहा है।

भारत की मातृभाषा के साथ हो रहा अन्याय

संस्कृत विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ जो घटना हुई उसे देखने के बाद बार बार मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है, यह हमारी ज्ञान की भाषा है, यहां तक की इसी भाषा में वेद, पुराण, रामायण और महाभारत की रचना की गई। लेकिन आज वर्षों बाद भी भारतीय संस्कृत भाषा के साथ हो दुर्व्यवहार हो रहा है वह चिंता जनक है। यह बात सिर्फ युवाओं के रोजगार से जुड़ा चिंता का विषय नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ा चिंता कारण है कि हमारी भाषा का अस्तित्व खतरे में आ गया है। चंद अफसरों की लापरवाही और उदासीनता के कारण आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है।

धर्मगुरु, शिक्षक और प्रोफेसर बन सकते हैं

अगर संस्कृत में शास्त्री या आचार्य तक की पढ़ाई विद्यार्थी ने कर ली है तो वह आर्मी में धर्मगुरु बन सकता है। स्कूलों में वर्ग एक, दो, तीन का शिक्षक बन सकता है और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले तो कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आयुर्वेद की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बागभट्ट जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा वास्तु ज्योतिष शास्त्र, योग, वैदिक गणित, वेद विज्ञान, इतिहास, 18 पुराण के अध्ययन से अलग-अलग क्षेत्र में जाने की अपार संभावनाएं हैं. शास्त्री की पढ़ाई करने के बाद जिस तरह से अध्यर्थी ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी एसएससी, एमपीपीएससी या अन्य कंपटीशन एग्जाम दे पाते हैं, उसी तरह शास्त्री के अभ्यर्थी भी एग्जाम देने के पात्र होते हैं।

युद्धों से सबक ले गरीब दुनिया

रघु ठाकुर
विचारक

इजरायल के 1200 लोग हमास के हमलों में मारे गये और अभी तक अधिकृत सूचना के अनुसार फिलिस्तीन के 42 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वैसे भी युद्ध में मरने वालों की सही संख्या की गणना कठिन होती है। गाजा पट्टी का अधिकांश हिस्सा हमास के कब्जे से निकल चुका है और अब ट्रम्प ने तो फिलिस्तीनी आबादी को वहाँ से हटाकर अन्यत्र समीपी देशों में बसाने की न केवल कोशिश रूपी घोषणा कर दी है, बल्कि इस योजना पर अमल भी शुरू कर दिया है। चर्चा शुरू हुई है कि अब अरब देश भी इस्लामिक आधार पर फिलिस्तीन के साथ एकजुट होने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। अगर यह हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है।

इस समय दुनिया के पटल पर तीन घटनाएं मुख्य चर्चाओं के बिन्दु हैं। एक यूक्रेन और रूस का युद्ध, दो हमास-इजरायल का संघर्ष और तीसरा अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का सनकी परन्तु बेबाक व्यवहार। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के चलते कई लाख लोग मारे जा चुके हैं और बड़े पैमाने पर धन-सम्पत्ति की बर्बादी हुई है। हालांकि पिछले कई वर्षों से चल रहे युद्ध के बावजूद भी रूस अभी तक जीत नहीं सका है, केवल यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर सका है। कई सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 कि.मी. क्षेत्र पर ही वास्तविक कब्जा कर सका है। यह तथ्य है कि, युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, बल्कि रूस बनाम अमेरिका और यूरोप के बीच है। यूरोप तो नाटो में यूक्रेन को शामिल करने के लिए पूर्णतरू कटिबद्ध है पर अमेरिका दोहरा खेल खेल रहा है। युद्ध विराम कराने का दावा करता है और कभी रूस और कभी यूक्रेन की तरफदारी करता है। शायद यूरोप और अमेरिका का सहारा है इसलिये यूक्रेन टिका हुआ है। यूरोप के देश चाहते हैं कि यूक्रेन जो वस्तुतः यूरोप का ही एक हिस्सा है, नाटो में शामिल हो और उसकी सुरक्षा छतरी के बीच सुरक्षित हो। यूरोप के देश, व नाटो के सदस्य, यूक्रेन को आर्थिक सामरिक मदद कर रहे है।

पिछले 5 वर्षों से अमेरिकी प्रशासन भी यूक्रेन को भारी आर्थिक और सामरिक मदद देता रहा। डोनाल्ड ट्रम्प के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को 31 लाख करोड़ रुपया की मदद दे चुका है। यह राशि भारत के राष्ट्रीय बजट से लगभग आधा से ज्यादा होती है। रूस ऊपरी तौर पर तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रोकना चाहता है, परन्तु उसकी वास्तविक इच्छा यूक्रेन को हड़पने और रूस में वापिस मिलाने की है। यूक्रेन का खनिज अमेरिका-रूस-यूरोप तीनों को ललचाता है। इस मामले में चीन रूस के साथ है। शायद चीन का सोचना है कि अगर रूस यूक्रेन को हड़प सका तो फिर चीन के लिए ताइवान को हड़पने के लिये एक मजबूत तर्क मिल जायेगा।

वैसे तो डोनाल्ड ट्रम्प की भाषा एक तानाशाह जैसी लगती है, जो तीखा और कठोर बोलने के अभ्यस्त है। शायद अमेरिकी इतिहास में ऐसा राष्ट्रपति कोई और नहीं हुआ होगा, परन्तु मुझे डोनाल्ड ट्रम्प तानाशाह नजर नहीं आते। क्योंकि तानाशाह कभी भी लोकतंत्र व संवाद पसंद नहीं करता। जबकि ट्रम्प हर दिन बहस मुबाहसे में अपने नस्ली भाईयों, मित्रों, सहयोगियों से सार्वजनिक रूप से उलझते हैं। परन्तु कुछ समय बाद पूर्ववत् मित्र-शुभचिंतक बन जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा में जो संयुक्त पत्रकार वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई उसमें ट्रम्प यूक्रेन को मदद देने के बारे में अमेरिकी मदद की चर्चा कर रहे थे और उत्साह में आकर बोले कि श्केवल अमेरिका ने ही यूक्रेन की मदद की है। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि आप गलत हैं। फ्रांस और यूरोप के देशों ने भी मदद की है ।

28 फरवरी को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच बातचीत में नोंक झोंक हुई। यहां तक कि पत्रकार वार्ता में भी तीखी बहस हो गई। ट्रम्प ने यह भी कहा कि जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ऊँची आवाज में बात कर अमेरिका का अपमान किया है। परन्तु एक चतुर व्यापारी की तरह ट्रम्प ने यह तय करा लिया कि यूक्रेन 44 लाख करोड़ के खनिज अमेरिका को देगा और ट्रम्प ने प्रश्न बदलकर कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते परन्तु यूक्रेन को मदद देते रहेंगे और जेलेंस्की ने भी कहा कि हम अपने देश की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। जेलेंस्कि, के ट्रंप को उत्तर देने व दृढ़ता ने, उन्हें दुनिया में बहादुर सिद्ध किया है।

हालांकि ट्रम्प और जेलेंस्की या मक्रो के सार्वजनिक विवाद ने भी वांछित निर्णयों पर कोई प्रभाव नही डाला और सबने अपने-अपने हित साध लिये। तानाशाह अवज्ञा नहीं सहता, परन्तु लोकतांत्रिक मानस का व्यक्ति उस अवज्ञा को अपमान नही मानता तथा उसे मन में भी नही रखता। ट्रम्प का स्वभाव कुछ कुछ भारत के एक नेता स्व. बीजू पटनायक या पुराने सोशलिस्टों जैसा है, जो लड़ते हैं, वाद विवाद करते हैं, बिगड़ते हैं और फिर साथ हो जाते हैं। इसलिये ट्रम्प भले ही दुनिया को विश्व युद्ध के खतरे से डरायें परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि फिलहाल विश्व युद्ध नहीं होगा।

यूरोप और नाटो के देशों ने तो जेलेंस्की के अमेरिका से लौटने के बाद उनका स्वागत किया तथा यूक्रेन को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। यूरोप और अमेरिका में भी आर्थिक स्वार्थों और डॉलर के प्रयोग को लेकर तनाव है। इसलिए विश्व तानाशाही का कोई खतरा या विश्वयुद्ध की गंभीर चिंता अगर कभी भविष्य में हो तो यह स्वाभाविक है। पर मुझे वह रुसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग से ज्यादा नजर आती है, जिनका विश्वास अपने देश में या विदेश में लोकतांत्रिक संवाद में नहीं है। जेलेंस्की और ट्रम्प के सार्वजनिक विवाद संवाद ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि आज की दुनिया में कोई भी देश किसी दूसरे देश को न्याय और अन्याय के आधार पर समर्थन नहीं करता, बल्कि अपने हितों को ही सर्वोपरि मानता है। इजरायल और हमास के बीच के संघर्ष में तो ट्रम्प ने एक अलग ही लाइन ली है। निसंदेह हमले की शुरुआत, हमास ने की थी। अब उसका अन्त दुखदरू है। इजरायल के 1200 लोग हमास के हमलों में मारे गये और अभी तक अधिकृत सूचना के अनुसार फिलिस्तीन के 42 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वैसे भी युद्ध में मरने वालों की सही संख्या की गणना कठिन होती है। गाजा पट्टी का अधिकांश हिस्सा हमास के कब्जे से निकल चुका है और अब ट्रम्प ने तो फिलिस्तीनी आबादी को वहाँ से हटाकर अन्यत्र समीपी देशों में बसाने की न केवल कोशिश रूपी घोषणा कर दी है, बल्कि इस योजना पर अमल भी शुरू कर दिया हैं। चर्चा शुरू हुई है कि अब अरब देश भी इस्लामिक आधार पर फिलिस्तीन के साथ एकजुट होने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। अगर यह हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है।

अमेरिकी यूरोप और इजरायल तथा ईसाई और यहूदी के बीच के संबंध बहुत गहरे हैं। दरअसल्ल यही धुरी है जो दुनिया की अर्थ सत्ता,सामरिक सत्ता, राजनीति सत्ता, और कुछ हद तक वैश्विक राजनीति को नियंत्रित कर रही है। ट्रम्प का चातुर्य यहाँ भी प्रकट होता है कि उन्होंने यूएस के द्वारा भारत में मतदान बढ़ाने के नाम पर दिये गये 182 करोड़ के अनुदान को उन्होंने न केवल सार्वजनिक किया बल्कि उसके राजनैतिक लक्ष्य की ओर इशारा किया तथा नरेन्द्र मोदी को मित्र भी बता दिया। कई बार ऐसा लगता है कि ट्रम्प की शक्ल और बातें ऊपर से भले ही विदूषक जैसी लगती हों, परन्तु वह भीतर से वे बहुत चतुर और अमेरिकी हितों को सामने रख कर काम करते हैं। उन्होंने बंग्लादेश को भी 250 करोड़ रु. दिये जाने का खुलासा किया है। यद्यपि बंगलादेश के तख्तापलट में इस राशि का कितना इस्तेमाल हुआ है, वह शोध का विषय है। पर जिस प्रकार से बंगलादेश में शेख हसीना का अचानक सत्ता पलट हुआ, उन्हें भागना पड़ा, मोहम्मद युनुस की वापिसी हुई तथा अब इस तख्ता पलट के छिपे किरदार अपना राजनैतिक दल बना रहे हैं, उसमें एक जुड़ी हुई कड़ी देखी जा सकती है। बंगलादेश की घटनाएं भारत के लिये विशेष चिंता का विषय होना चाहिए। बंग्लादेश और पाकिस्तान के बीच उभर रहे रिश्ते कुछ नई दिशाओं के संकेत दे रहे हैं। पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही है और अब बंग्लादेश भी अघोषित सैन्य नियंत्रण में है। हालांकि मेरी समझ तो यह है कि पाक सैन्य अधिकारी और बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। ये दोनों देश फिलहाल मिल तो नहीं सकते पर सामरिक, विदेश नीति और व्यापारिक समझौता कर सकते हैं। पाकिस्तान की शक्कर की मिठास बंग्लादेश को भाने लगी है। इसकी भावी संभावनाओं और उसके परिणामों के बारे में भारत को सोचना चाहिये। बंगलादेश चीन से सटा हुआ है और चीनी प्रभाव से अगर पूर्णतरू प्रभावित नहीं है तो पूर्णतरू मुक्त भी नहीं है। म्यांमार की सैन्य सत्ता पहले ही चीन के नजदीक है। आंग सान सूकी अब दोनों ही धड़ों याने अमेरिका यूरोप व रूस के लिये ही अनुकूल और नहीं है। श्रीलंका में वामपंथी विचारों के अनुरा कुमार सत्ता में वापिस होकर आये हैं। अभी तो वे भारत के प्रति तटस्थ नजर आते है वैसे भी वह कोई वैश्विक प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है। पर यह दृष्टिकोण कब तक रहेगा कहना कठिन है। नेपाल भी मार्क्सवादियों की सत्ता नियंत्रण में है जो चीन के प्रभाव में है और अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते वे वैसे भी चीन से मधुर रिश्ते रखने को बाध्य हैं। हमारे देश के स्वयंभू विश्व गुरु इन वैश्विक घटनाओं में कहीं भी नजर नहीं आते और वैश्विक राजनीति से लगभग अलग से नजर आते हैं। विश्व की आर्थिक शक्तियों का कर्ज कैसी कीमत वसूलता है यह भारत को यूक्रेन की घटना से सीखना चाहिये। जिसे अपने देश की रक्षा के लिये लड़े जाने वाले युद्ध के लिये, दी गई मदद के बदले में अमेरिका को 44 लाख करोड़ का खनिज देना पड़ रहा है। भारत पर तो बगैर किसी युद्ध के ही इतना कर्ज है कि इस वर्ष केवल कर्ज और ब्याज की किश्त चुकाने पर भारत के कुल बजट का 20 प्रतिशत इस मद में चुकाना होगा या देना होगा। आगामी वर्षों में यह और बढ़ने वाला है। यूक्रेन, हमास और इजरायल के घटनाक्रम भारत और शायद समूची रंगीन गरीब दुनिया के लिये एक सबक है। बशर्ते इनके शासक मदमस्त होने के बजाय अपने देश और दुनिया के भविष्य के प्रति सावधान हो।

करीला मेला में आंगुतकों की सुविधाओं कोई खलल नहीं होने देंगे

अपर कलेक्टर ने समीक्षा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया

-संवाददाता

जगत प्रवाह. विदिशा। होली, रंगपंचमी पावन पर्व पर करीला में भरने वाले मेला में लाखों श्रद्धालुजन मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना व दर्शन के लिए शामिल होते हैं। आगंतुक श्रद्धालुगणों को किसी भी प्रकार की परेशानियां का सामना ना करना पड़े इसके लिए विदिशा जिले की राजस्व सीमा के अन्दर के मार्गों से संबंधित व अन्य वैकल्पिक प्रबंधों की समीक्षा अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर द्वारा की गई। जिले की सीमावर्ती बामौरीशाला ग्राम पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि जो-जो दायित्व पिछले वर्ष आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु सौंपे गए थे उन दायित्वों का क्रियान्वयन संबंधित विभागों के अधिकारी इस वर्ष भी और बेहतर तरीकों से क्रियान्वित करेंगे। अपर कलेक्टर ने जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित माता जानकी लवकुश मंदिरा करीला मेला में आंगुतकों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमियां नहीं होने देंगे। दो जिले विदिशा व अशोकनगर की सीमा पर स्थित माता जानकी लवकुश मंदिर करीला में श्रद्धालुगणों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के तहत स्वास्थ्य, यातायात, पेयजल आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, परिवहन, पार्किंग के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, सुरक्षा प्रबंध, फायर ब्रिगेड, वालिंटियर्स, कंट्रोल रूम, खोया-पाया केन्द्र के साथ-साथ अन्य प्रबंधों पर विचार विमर्श कर क्रियान्वित किया गया।

प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़

- देश में धान की सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य
- प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य
- जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणीय राज्य
- कोयला उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
- देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य
- लौह अयस्क उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
- देश में टीन धातु का नंबर वन उत्पादक राज्य
- सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावरहाउस

R.O.No.: 13159/1

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)